

शहर में बिल्डिंगों में लगे टॉवरों से हो सकता है बड़ा हादसा



इनका कहना है

उत्तर प्रदेश के रेत माफिया के द्वारा मध्य प्रदेश की रुन्झ नदी की सीमा में अवैध उत्खनन करने पर कार्यवाही की जाएगी सीमांकन से सीमा चिन्हित हो गई रुन्झ नदी में उत्तर प्रदेश का अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इन्फेक्शन की आशंका

मोबाइल टॉवर के आसपास रहने वाले व्यक्तियों के लिए टावर से उत्सर्जित होने वाले विकिरण मुख्यकी तरंगों उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। व्यक्ति कैंसर, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हो सकता है गर्भवती महिलाएँ या ऐसे मरीज जिन्हें पेसमेकर लगा है उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इस मामले पर गठित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता का माप 450 माइक्रो वॉट सेमी वर्ग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि तीव्रता बढ़ ती है तो वह कोषी मानव स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती है।

जिना काम के हैं आहरित कर हमज करने के लिए कह दिया जाता तो तैयार न होंगी। जल्दी केवल यही है कि उनकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। किसे कितना कमीशन मिलेगा, जब इसकी फिक्रसंग हो जायेगी तो फिर कागज में काम पूरे लगते हैं, सप्टाइज होने लगती है जनात को पता ही नहीं चलता कि कितनी सड़कें कागजों में बनकर पूरी हो चुकी हैं, 90 प्रतिशत से भी अधिक व्यय से भी अधिक व्यय होने के बाद बताया जा रहा है कि काम प्रगति पर है। कितनी पंचायतों के कार्यों की फोटो पोर्टल में चप्सा की जाती है। फर्जी व कागजी प्रगति तो अपने आप बोलती है।

किसी भी वेण्डर के खिलाफ विभागीय स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक किसी भी जनपद सीईओ की जांच में, आरईएस की तकनीकों जांच में, जिला पंचायत स्तर की जांच में भी वेण्डरों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जबकि वेण्डर से ही अल्पमिता का रास्ता खुलता है। फर्जी बिल वेण्डर के माध्यम से ही जारी होते हैं। करोड़ों का आनलाईन या ऑफलाईन आहरण वेण्डरों के ही खातों किया जाता है। इसके बाद फिर किसी निकसी कर बंटवारा किया जाता है। यदि वेण्डर की जांच हो जाय, उसकी हैसियत की जांच हो जाय, उसके दुकान, स्टोर आदि की जांच स्थापन हो जाय तो पता चलेंगा कि जिन वेण्डरों के नाम पर करोड़ों की राशि ट्रांसफर हो रही है उसके पास तो सत्याई के नाम पर सामग्री ही नहीं उपलब्ध नहीं है, उसके पास इस बात के भी प्रमाण नहीं मिले कि वह सत्याई करने के लिए सामग्री कहाँ से परचेन कर रहा था। उसके पास जीएसटी के रिटर्न भरने का भी रिकार्ड नहीं मिलेगा। उसके पास यदि मिला तो केवल बिल जारी करने वाला फर्जी बिल बुक जिसके माध्यम से महंगे करोड़ों का खेल कर लेता है।

सिंधानिया इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षुओं का प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन



तैयारीयों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। डीपीसी अजय कुमार गुप्ता द्वारा विद्यार्थियों के परिश्रम और शिक्षकों के मार्गदर्शक की सराहना की गई। उपस्थित समस्त छात्र-छात्राओं,

नवभारत यूज
पत्रा 19 फरवरी । इंडिया स्किल कम्पटीशन 2025-26 का क्षेत्रीय स्तर का आयोजन गांधीनगर गुजरात में 15 फरवरी से 18 फरवरी तक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ ।
प्रतियोगिता का शुभारंभ 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री द्वारा किया गया । 16 एवं 17 फरवरी को आयोजित इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता में कुल 63 विभिन्न स्किल्स पांच राज्यो (राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोआ) के कुल 300 से भी अधिक प्रतिभागियों ने अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया । इस प्रतियोगिता में यदुपति सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमानगंज पन्ना के प्रशिक्षुओं ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट



प्रदर्शन किया। संस्थान के प्रतिभागियों ने ब्रिकलेयिंग, रिन्यूबल एनर्जी और वाल एंड फ्लोर टाइलिंग में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता में संस्थान के प्रशिक्षु अजय अहिरवार ने ब्रिक लेयिंग प्रतियोगिता ट्रेड में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेपाल सिंह ने वाल एवं फ्लोर टाइलिंग में स्वर्ण पदक अर्जित किया। स्वर्ण पदक विजेता प्रतिभागियों को गुजरात सरकार के कौशल मंत्रालय की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप 75,000/- का चेक प्रदान किया गया। संस्थान के प्राचार्य मनीष कुमार बुनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह उपाख्यं न केवल संस्थान बल्कि मध्य प्रदेश राज्य के लिए भी गौरव का विषय है। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य को कामना की।

जागरूकता के लिए स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन

जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को जाति प्रमाण पत्र भी कार्यालय प्रमुख से सत्यापित कर संलग्न करना होगा।

निर्धारित प्रारूप में आवेदन तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। म.प्र. शासन वित्त विभाग के निदेशानुसार स्थानीय निकाय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के लिपिकवर्गीय कर्मचारी, जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है, वे भी प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण शुल्क 5 हजार रुपये का चालान सत्र में प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

नवभारत न्यूज
पत्रा, 19 फरवरी। छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य पर स्लेगन प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य डॉ एस डी चतुर्वेदी के संस्करण एवं भारतीय ज्ञान परंपरा की संयोजक डॉ शुभम पाठक के निदेशन में संपन्न हुआ।

विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्लेगन प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व से परिचित कराना तथा सकारात्मक

आंगनबाड़ी केन्द्रों में शत प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति

नवभारत न्यूज
पत्रा, 19 फरवरी। मुख्य सचिव
अनुराग जैन ने आंगनबाड़ी
केन्द्रों में बच्चों की शत प्रतिशत
उपस्थिति सुनिश्चित कराने के
निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि बच्चों को
प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुहैया
कराना आवश्यक है। इसके
लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में शत
प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित
होना चाहिए।
आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों
की शत प्रतिशत उपस्थिति के
संबंध में शिक्षा और महिला एवं
बाल विकास विभाग संयुक्त रूप
से कार्य करें। उन्होंने कहा कि
अप्रैल माह से जालू होने वाले
नवीन शिक्षा सत्र में शत प्रतिशत

छात्र-छात्राओं को स्कूलों में प्रवेश
दिलाने के लिए कार्ययोजना तैयार
करें। स्कूलों में प्रवेश से वंचित
छात्र-छात्राओं की संख्या नगण्य
हो। इसके सतत प्रयास किए जाएं
तथा शैक्षणिक कैलेंडर का पालन
सुनिश्चित किया जाए। मुख्य
सचिव श्री जैन ने वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के
सभी कलेक्टरों एवं प्रमुख
अधिकारियों को उक्ताशय के
निर्देश दिए। इस अवसर पर
कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी व्हीसी
कक्ष में अलीकृत रुपा परमार,
पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू,
जिला पंचायत सीईओ उमराव
सिंह मारुवी, अवर कलेक्टर
मधुवंतराव धुवें, अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक वंदना चहान सहित

अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने स्कूलों में बालिकाओं के लिए बनाए जा रहे बालिका शौचालयों के निर्माण की प्रगति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि बालिका शौचालयों का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए तथा यह कार्य मार्च माह के अंत तक पूर्ण हो जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे शीघ्रतापूर्वक भवनों की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ मरम्मत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल भवनों में किसी भी प्रकार की दुरुवस्था न हो, यह सभी कलेक्टर सुनिश्चित करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जिलेवार समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोगों को कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए अनंतर प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अधिकार से अधिक प्रकरण तैयार कर बैंकों को प्रेषित कराएँ तथा हितवादीयों को बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराकर कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए सतत रूप से प्रोत्साहित करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि कलेक्टर्स शासन द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएँ और लोगों को आमदनी बढ़ाने के सतत प्रयास करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री कृषक मित्र पूर्ण योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री कृषक मित्र पूर्ण योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएँ तथा इस योजना के संबंध में किसानों को समुचित जानकारी मुहैया कराएँ तथा किसानों को इस योजना से लाभ उठाने के लिए सतत रूप से प्रोत्साहित भी किया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने रुफटॉप सौर योजना की भी जिलेवार समीक्षा की तथा इस योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने, योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा योजना का लाभ लोगों को दिलाने के भी निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टरों को निर्देश दिए कि लोक सेवा प्राधिकरण के तहत लोगों को सहजता से सेवाएँ मुहैया कराएँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव द्वारा अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।